जो 6,511 वेकेंसीज हैं, उनको आगे फिल-अप करने के लिए उन्होंने रीकमंड किया है, तो Delhi Subordinate Services Selection Board उसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंडक्ट करता है। उसमें से जो promotional vacancies हैं, उन्हें अलग से रखा है, जहां प्रमोशन करके हम लोग उस पोस्ट पर रखेंगे, उसका अलग है, वह recommendation में नहीं आता है इसलिए promotion का प्रोविजन अलग से है।

LPG subsidy into consumer's bank accounts

*502.SHRI A.U. SINGH DEO: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the State/Union Territory-wise number of consumers getting LPG subsidy directly into their bank accounts in the country;

(b) whether Government has received complaints from consumers regarding getting lesser amount of subsidy into their bank accounts, if so, the details thereof and action taken by Government in this regard;

(c) whether Government has taken a decision to increase number of subsidized LPG cylinders from 9 to 12 per consumer per year and to delink subsidy on the fuel for Aadhaar cards; and

(d) if so, the details there of and financial loss likely to be incurred by Oil Marketing Companies (OMCs) as a result thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Scheme of Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL), which was launched in 291 Districts of the Country has been kept in abeyance till further orders as per Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA) decision dated 28.02.2014 and the system of providing subsidized cylinders to all domestic LPG consumers on payment of the applicable subsidized price for each such cylinder has been re-introduced in all the above DBTL districts, as per the consumer's entitlement of subsidized cylinders.

Some complaints relating to cash transfer in LPG and Aadhaar seeding were received. As and when the problems were reported process improvements were discussed with various stakeholders such as Banks, NPCI and UIDAI and necessary action taken.

Steps to resolve complaints, *inter-alia,* include access to seeding data on OMC portals/ call centres, provision of informing subsidy transfer details and grievance redressal through call centres.

Government has revised the cap on supply of subsidized LPG cylinder per domestic connection from 9 to 11 *w.e.f.* 01.02.2014 and 12 from the year 2014-15. Based on the consumption pattern of 2013-14 and average subsidy rate of subsidized LPG cylinder during the year 2013-14 @ ₹ 522.10 of subsidy per cylinder, approximate additional subsidy burden on the change of cap from 9 to 12 is estimated at ₹ 2443.50 crore.

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, a statistical analysis carried out by the Ministry of Petroleum and Natural Gas indicated an 18 per cent reduction in sales of domestic LPG cylinders due to the launch of DBTL (Direct Benefit Transfer for LPG) and capping on the number of cylinders. LPG subsidy burden in 2013-14 was ₹ 464 billion. The DBTL along with capping can lead to about annual savings in subsidy of ₹ 65 billion, which will drastically reduce burden on the exchequer. In this context, Sir, Dhande Committee in his Report has made several recommendations for smooth functioning of DBTL such as setting up of Central Grievance Redressal mechanism, targeted enrollment of LPG consumers ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: What is the question? Please don't read a statement. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, my question is: The previous Government had said that this scheme was a game changer. What were the reasons that the scheme was kept in abeyance and what is the loss to the exchequer as a result of this decision? When will it be reintroduced in the context of Odisha and India?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न पूछा है । जब डी.बी.टी.एल. योजना पिछली सरकार के समय में 1 जून, 2013 को शुरू की गयी, तब उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी जोड़ा गया कि यह गेम चेंजर हो सकता है । हो भी सकता था, लेकिन उसकी जो तैयारी होनी चाहिए थी, उस कार्यक्रम को, डी.बी.टी.एल. को लॉच करने से पहले जो तैयारी होनी चाहिए थी, वही नहीं की गयी। कई सारे tax regime जो देश के अंदर हैं, उनकी कोई uniformity नहीं थी, उसे एड्रेस नहीं किया गया। 291 जिलों में 6 फेज़ेज़ में उसे लागू किया गया, लेकिन इसमें जो आधार कार्ड बनने चाहिए थे, वे भी नहीं बन पाए थे, जो grievance redressal machanism खड़ा होना चाहिए था, ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज़, बैंक्स, यू.आई.डी.ए.आई. और एन.पी.सी.आई., जो गेटवे बनाना चाहिए था, आधार पेमेंट ब्रिज बनाना चाहिए था, उसकी पूरी तैयारी नहीं की गयी थी। उसके उपरांत उसके कुछ कानूनी पहलू भी थे। 15 राज्यों में, 15 हाई कोर्ट्स में केस लगे थे, सुप्रीम कोर्ट में वह केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने दो बार उसके ऊपर टिप्पणी की, एक बार सितम्बर, 2013 में और फिर मार्च, 2014 में एक बार की। प्रथम दृष्टि में यह लगता है कि इसको एक महत्वाकांक्षी योजना बनाया जा सकता था। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, इसके अंदर करप्शन को रोका जा सकता था, कस्टमर को अच्छे बेनिफिट्स दिए जा सकते थे, लेकिन चुनाव से पहले राजनैतिक हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी सरकार जल्दबाजी में इसको लायी थी ...(**व्यवधान**)... अच्छी स्कीम होते हुए भी यह लागू नहीं हो पायी। उन्हीं की सरकार के समय में उन्हें बंद करना पड़ा। ...(**व्यवधान**)... यह इसकी पृष्ठभूमि है।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, स्पेसेफिक जवाब देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: That is not a part of your answer, please. ...*(Interruptions)*... Your second question. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.U. SINGH DEO: Sir, under the past subsidy regime, there has been abundant dual pricing in the market, leading to corrupt misuse of subsidized LPG for non-domestic purposes. The Finance Minister in his Budget proposed overhauling the current petroleum subsidy regime to make it more targeted for providing protection to the marginalized, the poor, SCs/STs.

My question is: Hon. Petroleum Minister, Shri Dharmendra Pradhan, in a statement projected a system where the poorest get LPG at the cheapest rate and where subsidies progressively reduce as one moves up the income scale. While this is essential for reducing subsidy burden in order to obtain the 4.1 per cent fiscal deficit ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One question, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.U. SINGH DEO: What steps has the Government undertaken or proposed to undertake to identify the targeted beneficiaries so as to ensure benefits to the right persons?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति महोदय, देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब देश के सामने अपना बयान रखते हैं, तो एक विषय पर जोर देते हैं कि हम जनता को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुशासन देंगे, गुड गवर्नेंस इस सरकार की प्राथमिकता है। यह सरकार 'आधार' के माध्यम से हो या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, दोनों को काम में लाते हुए, हम कोई राजनैतिक उद्देश्य से चीजों को नहीं देखते हैं। पिछली सरकार ने अगर अच्छा काम शुरू किया ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please focus on the question. ...*(Interruptions)*...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : उसे आगे ले जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी पाटिल : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : अभी बजट के समय में देश के वित्त मंत्री जी ने टारगेटेड कस्टमर के बारे में कहा ...(**व्यवधान**)... कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please focus on the question.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सभापति जी, माननीय मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति महोदय, उनको सच सुनने की हिम्मत नहीं हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : I would expect the hon. Members to ask answerable questions, as they are, not going to the wider issues.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, नई सरकार जनता के अंदर सही तरीके से आवंटन के लिए आई.टी. टेक्नोलाजी को माध्यम बनाते हुए, चाहे यू.आई.डी.ए.आई. हो, चाहे एन.पी.आर. हो ...(**व्यवधान**)... दोनों के आधार पर हम नये तरीके से टारगेटेड कस्टमर तक जायेंगे, करप्शन को रोकेंगे और गुड गवर्नेंस की डिलिवरी करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN : We are not discussing that. Shri Hanumantha Rao.

श्री आनन्द शर्मा : चेयरमैन सर, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल साफ है, जो भी सदस्य हैं, उनकी आप रक्षा करें, जिन्होंने प्रश्न पूछा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, आपका सदस्यों को निर्देश होता है कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करिए।

MR. CHAIRMAN: Yes, I know that.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप मंत्रियों को भी तो निर्देश दीजिए कि ये भी प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर दें। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Yes, agreed. Now, Shri Hanumantha Rao.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Mr. Chairman, Sir, I will straightway ask a pointed question. After the issue of AADHAR cards, people went to the gas agencies. Then, the amount of subsidy was transferred to their bank accounts. But in some of the places, the amount has not yet come in the bank accounts. People are suffering due to this. Moreover, it was promised to provide 12 cylinders instead of 9 cylinders.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI V. HANUMANTHA RAO: I would like to know whether they will provide 12 cylinders. At the same time, the amount of subsidy still has not come in the bank accounts, especially in Andhra Pradesh. Has the Minister got any complaint from Andhra Pradesh in this regard?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न उठाया है। मैं मानता हूं कि अगर पूरी तैयारी से इसे करते, तो बैंक के अंदर यह मसला नहीं उठता। इसीलिए इसको पिछली सरकार द्वारा बंद करना पड़ा, पिछली सरकार की regime में ही इसको बंद करना पड़ा। माननीय सदस्य ने आन्ध्र प्रदेश के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछा है, तो पुराना कोई बैकलॉग होगा, तो उस पर हम ध्यान देंगे। हम कंज्यूमर के पास कैसे डिलिवरी हो, इसकी चिंता करेंगे। उन्होंने जो 9 से 12 सिलेंडर करने की बात कही है, अभी की सरकार जो 12 सिलेंडर की अलॉटमेंट है, उसको जारी रखेगी।

SHRI S. THANGAVELU: Sir, the Government is giving subsidy in the form of money transferred to the beneficiary's bank account. My question is whether the

Government has asked public sector oil companies to adopt any mechanism to ensure timely transfer of subsidy to the correct accounts?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, देश के अंदर कस्टमर बेस को digitize करने की बात पिछली सरकार ने भी चलाई थी। यह सैद्धांतिक तरीके से एक अच्छी योजना है। हमारी इतनी ही आब्जर्वेशन उसमें बन पाई कि इसको थोड़ा आधे-अधूरे तरीके से लाया गया था। जो माननीय सदस्य ने पूछा है आने वाले दिनों में सरकार सारे बेनिफिट को एक अच्छे तरीके से, बैंक अकाउंट के जरिए से कस्टमर तक पहुंचाए, इसके लिए हम सारे कदम उठा रहे हैं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I appreciate the hon. Minister's statement that the programme, which was started in a very halfhearted manner, without preparation and absolutely thoughtlessly, is now being improved upon. That is fine.

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But, for DBTL, to be effectively put in motion, I think three important requirements are there. One is that every body must be covered under AADHAR. All the poorer persons, for whom the subsidy is meant, should have bank accounts. Thirdly, both the things should be linked together. Kindly give us a timeframe as to when you are going to make it foolproof. Kindly give us the present status of inclusion of poorer people having bank accounts and also covered under AADHAR. What is the percentage of poor population covered under these two things? Also tell us whether they are linked together because in a number of observations by the Parliamentary Standing Committee on Petroleum, it has been noted that there are AADHAR cards and there are bank accounts, but they are not linked. At least, more than 50 per cent of the population does not have any bank account at all, and, they actually require the subsidy.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: What is the percentage of default in bank accounting, what is the percentage of default in Aadhar linkage and what is the percentage of default of Aadhar and Bank account linkage. Only after that, this scheme can become foolproof.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सभापति जी, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि इसकी तैयारी क्या है? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें जो मूल बात है, Scientific Payment Gateway is the issue. उसमें कितने लोगों तक आधार कार्ड हो या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, दोनों की जो digitalized list है, इसकी तैयारी क्या है? सभापति जी, देश में लगभग 95 प्रतिशत जिलों में इसका काम शुरू हो गया है। 20 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक 29 जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। अभी-अभी नई सरकार आने के बाद inclusive growth को 70 प्रतिशत तक करने के लिए जो रुपया देने की स्कीम है, उसमें सारे लोगों को बैंक एकाउंट हो, इसमें दो ही चुनौतियां हैं - जिनको सुविधा मिलेगी उनको सब्सिडी डिलिवर की जाएगी, उनके नाम priority के हिसाब से आ जाएं और सबके पास बैंक एकाउंट हो जाएं।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my question was specific. What is the number

of those who are excluded from having a bank account till now, and, what is the number of those who are excluded from being linked up with the Aadhar till now? What is the coverage of DBT scheme? ...*(Interruptions)*... My question was specific. Please reply to that.

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, यह एक जेनरिक प्रश्न है। अगर आप अनुमति दें, तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से डिटेल्स भी दे सकता हूं।

श्री सभापति : आप उनको डिटेल्स दे दीजिए।

श्री धर्मेंद्र प्रधान : मूल विषय है, बैंक एकाउंट और आधार लिस्ट हो या NPR लिस्ट हो, सरकार ने इन दोनों की तैयारी शुरू कर दी है।

Inflow of FDI

*503.SHRI C. M. RAMESH: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the year-wise, country-wise and sector-wise Foreign Direct Investment (FDI) into the country since opening up of the Indian economy in 1991;

(b) whether it is a fact that FDI inflow in the recent past has come down, if so, reasons therefor;

(c) the remedial measures Government proposes to take to attract more FDI; and

(d) the year-wise and country-wise details of FDI inflows of major developing and developed countries during the last ten years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total amount of FDI inflow (FDI equity + Equity capital of unincorporated bodies, Re-invested earnings and other capital) received since August, 1991 to May, 2014 is US$ 348.41 billion. The year-wise details of FDI inflow for the period August, 1991 to May, 2014 are given at Statement-I (*See* below). The country-wise and sector-wise information on FDI inflow are available only for FDI equity inflows (FIPB/SIA approval route, RBI Automatic route and Acquisition of Existing Shares) w.e.f. April, 2000 and relevant details are given at Statement-II & III respectively (*See* below).

(b) During the last 3 years FDI inflow has fluctuated. FDI inflow has decreased by 26.33% during the Financial Year 2012-13 in comparison to F.Y. 2011-12 and increased by 6.12% in 2013-14 in comparison to 2012-13. Under the liberalized economic environment, investment decisions of investors are based on the macro-economic policy